

अल्बर्टा में पुनर्स्थापनात्मक न्याय को मजबूत करना

06 नवंबर, 2022 [मीडिया पूछताछ](#)

अल्बर्टा की सरकार पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 720,000 डॉलर का निवेश कर रही है।

अल्बर्टा स्थित गैर-लाभकारी संगठनों और नगर पालिकाओं के लिए \$720,000 की पुनर्स्थापनात्मक न्याय निधि प्राप्त करने के लिए आवेदन अब खुले हैं। यह अनुदान औपचारिक न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों को हल करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों का समर्थन करता है, जिसके परिणामस्वरूप सार्थक समाधान और सामुदायिक एकीकरण होता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय अपराध में शामिल सभी लोगों को अपराध के प्रभावों पर सहयोगात्मक रूप से चर्चा करने और हुए नुकसान की मरम्मत के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करके जवाबदेही, उपचार और सुलह को बढ़ावा देता है।

"पुनर्स्थापनात्मक न्याय हमारी न्याय प्रणाली का एक मूल्यवान हिस्सा है। यह उन लोगों को अवसर प्रदान करता है जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया है और जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, ताकि वे न्याय, जवाबदेही और सुलह की दिशा में अपनी यात्रा में सक्रिय भागीदार बन सकें। अल्बर्टा पुनर्स्थापनात्मक न्याय अनुदान समुदायों को ऐसे कार्यक्रम विकसित करने और लागू करने में सशक्त बनाएगा जो शामिल सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएँ।"

मिकी अमेरी, न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल

समुदाय-आधारित गठबंधन, पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन, स्वदेशी समुदाय, युवा न्याय समितियां और नगर पालिकाएं सहित पात्र आवेदक 50,000 डॉलर तक के व्यक्तिगत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन 6 दिसंबर तक खुले हैं।

त्वरित तथ्य

आवेदक अल्बर्टा में रहना चाहिए और निम्नलिखित में से एक होना चाहिए:

- पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन और/या पंजीकृत चैरिटी (अच्छी स्थिति में)
- समुदाय-आधारित गठबंधन और नेटवर्क समूह जिनके पास एक नामित वित्तीय एजेंट है
- स्वदेशी समुदाय, जिसमें बैंड और आदिवासी परिषदें शामिल हैं
- युवा न्याय समितियाँ जो वर्तमान में अपने मुख्य कार्य के लिए धन प्राप्त कर रही हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं, लेकिन केवल उन गतिविधियों के लिए जिन्हें वर्तमान में न्याय मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है
- नगर पालिकाएँ

संबंधित जानकारी

- [अल्बर्टा रिस्टोरेटिव जस्टिस ग्रांट](#) आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

मीडिया पूछताछ

चिनेन्ये अनोकवुरु

780-720-1915

वरिष्ठ प्रेस सचिव, न्याय